[श्री रजनी रंजन साहू]

उन परिवारों के मेल मैंबर्ज हैं उनका आय है जो वे स्वयं अर्जित करते हैं। उप सभाध्यक्ष महोदय कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से उनका ग्रामीण जीवन ऊपर उठाया जा सकता है हां एक बात अवश्य ध्यान में रखने में योग्य है कि सूत कातने वालों को मार्केटिंग की व्यवस्था कमीशन को करनी चाहिए। उसे उनकी क्वालिटी पर निगरानी के साथ-साथ उसकी क्वालिटी मैनटेन भी रहे इसकी व्यवस्था खादी कमीशन को करनी चाहिए। उनकी फिनिश गुड्ज में रिटेल आउटलैट की व्यवस्था तथा रिसर्च एंड डिवैलपमेंट की भी व्यवस्था खादी कमीशन को करनी चाहिए तभी जो लोग सूत का उत्पादन करते हैं, जो लोग खादी मिशन के तहत गरीबी की रेखा से ऊपर कार्य कर रहे हैं उनका काम सुचारू रूप से चल सकेगा। मैं खादी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंसा की सराहना करता हूं। उन्होंने यह कहा है कि—इस शताब्दी के अन्त तक देश का प्रत्येक गांव एक ग्रामीण इकाई की तरह आ जाये। इसमें कम से कम 20 से 30 प्रतिशत तक विलेज आर्टिजन इनकम लेवल, इसमें लगे लोगों की आय गांव में आधुनिक तकनीकी से काम करने वाले किसानों के बराबर हो जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय लघु उद्योग से यह उद्योग भिन्न है। अतः इसे पेकेज आफ असिस्टेन्स भी लघु उद्योग से भिन्न मिलनी चाहिए। भारत सरकार एवम् राज्य सरकार के वित्तीय निगम को भी इसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा ग्रामोत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें तालमेल हो उसमें एक तादात्म्य स्थापित हो। ऐसी एक कंप्रहेन्सिव रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए ताकि अलग-अलग कुंडली और अलग अलग राग न हो सके और डवलपमेंट का काम गांव गांव में समुचित रूप से चल सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इस बात की मैं सराहना करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन एवम् विक्रय में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 16.47 करोड़ (**समय की घंटी**) का उत्पादन हुआ और छठी योजना में 1040 करोड़ का उत्पादन हुआ है ...(**समय की घंटी**)...

बस, एक मिनिट में खत्म कर लेता हूं। इस की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जितनी बढोतरी होनी चाहिए जितनी दूसरे उद्योगों में हुई है वैसी नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और अपने साथियों के साथ आवाज मिलाकर कहना चाहूंगा कि खादी कमीशन का खादी मिशन की तरह काम करना होगा और भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है **इस पर** पुनः विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The hon. Minister will reply on Monday.

ANNOUNCEMENT RE. ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 5th March, 1987, allotted time for Govern-

ment Legislative and other Business as follows: —

	BUSINESS	*TIME ALLOTTED*
1	Consideration and return of the Cotton, Copra and Vegetable Oils Cess (Abolition) Bill, 1987, as passed by the Lok Sabha.	2 hrs.
2-	Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Delhi Municipal Corporation (Amend ment) Ordinance, 1987 and consideration and passing of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1987.	1 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING THE 9TH MARCH,

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB):

Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 9th March, 1987 will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. General discussion on the General Budget for 1987-88.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday the 6th March 1987.